Ref No: PSB/HO/Shares Cell / 25 /2025-26 **July 08, 2025**

To,

BSE Limited, **Department of Corporate Services,** 25th floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001. **SCRIP ID : PSB** **SCRIP CODE : 533295**	**National Stock Exchange of India Ltd.,** Exchange Plaza, C – 1, Block – G, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051. **SYMBOL: PSB SERIES: EQ**

Dear Sir,

Reg: Newspaper Publication

This is in continuation to our intimation dated 07.07.2025 wherein it was, interalia, informed that the 15th Annual General Meeting of the Bank will be held on Tuesday, 05th August, 2025. In this regard, Bank has also published a notice in the newspapers.

A copy of newspaper publication in Business Standard (Hindi and English editions) on 08.07.2025 is forwarded for your reference.

You are requested to take a note of the same.

Yours faithfully

SAKET MEHROTRA
Digitally signed by SAKET MEHROTRA
Date: 2025.07.08 14:03:48 +05'30'

PUNJAB & SIND BANK H.O. Accounts & Audit Deptt. (Shares Cell) (शेयर कक्ष) EAST KIDWAI NAGAR, NEW DELHI

Saket Mehrotra
Company Secretary

दुर्लभ खनिजों को न बनाएं हथियार: मोदी

ब्रिक्स समूह के वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई के वैश्विक मानक बनाने का किया आह्वान

अर्चिस मोहन

ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ब्रिक्स सदस्य देशों से दुर्लभ खनिजों और प्रौद्योगिकी आपूर्ति चेन को सुरक्षित एवं विश्वसनीय बनाने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया है। रियो डी जनेरो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 'मजबूत बहुपक्षवाद, आर्थिक-वित्तीय मामले और एआई' पर आयोजित एक सत्र के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, 'यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कोई भी देश इन संसाधनों का इस्तेमाल अपने निजी स्वार्थ के लिए या दूसरों के खिलाफ हथियार के तौर पर न करे।'

दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले चीन के साथ भारत, रूस और ब्राजील 11 सदस्यों वाले ब्रिक्स समूह के संस्थापक सदस्य हैं। ब्रिक्स का 17वां सम्मेलन सोमवार को संपन्न हुआ। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की जगह प्रधानमंत्री ली कियांग ने रियो में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया।

एक दशक में सबसे लंबे दौरे पर 5 देशों की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री मोदी का उद्देश्य घाना, नामीबिया, अर्जेंटीना और ब्राजील में दुर्लभ खनिजों के आयात और प्रसंस्करण में आपसी सहयोग को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की इन महत्त्वपूर्ण संसाधनों के विकल्प की तलाश और ब्रिक्स सम्मेलन में उनकी टिप्पणियां इस संबंध में खास मायने रखती हैं कि चीन इन खनिजों की आपूर्ति को लगातार बाधित करने और इनकी कीमतें प्रभावित करने सहित इस क्षेत्र में जबरदस्ती की रणनीति पर चलते हुए एकाधिकार कायम रखना चाहता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में सुधार पर जोर दिए जाने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) ने विकासशील देशों की विकास संबंधी आकांक्षाओं में मदद करने के लिए मजबूत और विश्वसीनय विकल्प पेश किया है।

मोदी ने कहा कि परियोजनाओं को मंजूरी देते समय एनडीबी को मांग आधारित दृष्टिकोण अपनाने के साथ दीर्घावधि वित्तीय स्थिरता और स्वस्थ क्रेडिट रेटिंग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा, 'आंतरिक प्रणाली को मजबूत करने से परिष्कृत बहुपक्षवाद की दिशा में हमारे प्रयासों की विश्वसनीयता और बढ़ेगी।'

प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) में जो खिम, नैतिकता और पक्षपात के बारे में भी चिंताएं जाहिर की और सदस्य देशों से जिम्मेदार एआई मॉडल के लिए मिलकर काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगले साल 'एआई इम्पैक्ट समिट' भारत में आयोजित होगी। इसके अलावा हम 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करेंगे।

ब्रिक्स के रियो डी जनेरियो घोषणापत्र में 'बहुपक्षवाद शुल्क और गैर-शुल्क उपायों के बढ़ने पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। क्योंकि इससे व्यापार सीधे प्रभावित होता है और ये विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों से भी मेल नहीं खाते। ब्रिक्स के घोषणापत्र में अमेरिका का नाम नहीं लिया गया।

मलेशियाई प्रधानमंत्री से मिले मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन से इतर मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों ने आसियान-इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) की समीक्षा की। दोनों देशों ने 2009 में एफटीए समझौता किया था। अगस्त 2023 में दोनों पक्षों ने 2025 तक इस समझौते की संपूर्ण समीक्षा करने की घोषणा की थी।

हालांकि, दोनों पक्षों में मतभेदों के कारण एफटीए के लिए प्रस्तावित बातचीत रुक गई थी। भारतीय अधिकारियों के अनुसार, समझौता लागू होने के बाद भारत का निर्यात सालाना केवल लगभग 38-39 अरब डॉलर रहा, जबकि 10 सदस्यीय आसियान देशों से आयात बढ़कर 86 अरब डॉलर हो गया है।

चीन दुर्लभ खनिज के जानकारों को विदेश जाने से रोक रहा

सुरजीत दास गुप्ता

फॉक्सकॉन द्वारा भारत में आईफोन संयंत्रों में काम करने वाले चीनी तकनीशियनों और इंजीनियरों को स्वदेश भेजने के कुछ दिनों बाद अब दुर्लभ खनिज क्षेत्र में काम करने वाले जानकारों को विदेश जाने पर रोक लगा दी गई है।

चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने अपनी दुर्लभ खनिज कंपनियों से उन कर्मचारियों की सूची मांगी है जिनके पास दुर्लभ खनिज के प्रसंस्करण के साथ-साथ मैग्नेट बनाने में महारत है। इसके जरिये वह पक्का करना चाहता है कि जानकारों पर नजर रहे और वे विदेश न जा सकें ताकि जिन क्षेत्रों में चीन का दबदबा है उनकी प्रौद्योगिकी किसी और को न मिल सके।

मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ जानकारों से पासपोर्ट सरकार या कंपनी को सौंपने के लिए कहा गया है ताकि विदेश जाने पर उनकी हरकतों पर नजर रखी जा सके।

चीन की इस कवायद का सीधा अर्थ है कि भारतीय वाहन कंपनियों को अब मैग्नेट वाली पूरी मोटर का ही आयात करना होगा। इससे वाहन की लागत और भी बढ़ जाएगी। इसके जरिये चीन सरकार यह भी पक्का कर लेगी कि उस मैग्नेट का इस्तेमाल किसी अन्य उत्पाद में नहीं हो सके।

निर्यात पर नियंत्रण के तहत चीन ने इस साल अप्रैल की शुरुआत में भारत को दुर्लभ खनिजों का निर्यात कम कर दिया था। इस कारण अधिकतर वाहन कंपनियों के पास ज्यादा से ज्यादा जुलाई के अंत तक का स्टॉक बचा है। भारत में दुर्लभ मैग्नेट बनाने समेत तमाम विकल्पों में अभी काफी समय लग सकता है। इसलिए माना जा रहा है कि फिलहाल इलेक्ट्रिक मोटरों का आयात करना ही सही विकल्प रहेगा।

इलेक्ट्रिक दोपहिया बनाने वाली कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'मोटर के आयात से इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण की लागत बढ़ जाएगी। आयात की जाने वाली मोटरों की संख्या के हिसाब से लागत में 3,000 रुपये से 6,000 रुपये तक इजाफा हो सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटरों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना दुरुस्त करनी होगी और स्थानीय स्तर पर उत्पादन की सीमा को 50 फीसदी से कम करना होगा। पहले योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा मोटर का विनिर्माण भारत में ही होना है। ऐसा नहीं होता है तो प्रोत्साहन के लिए कोई पात्र नहीं रहेगा।' चीन यह भी देख रहा है कि दुर्लभ खनिजों के प्रसंस्करण और मैग्नेट विनिर्माण में उसका दबदबा कम नहीं हो। इसलिए वह देश के बाहर दुर्लभ मैग्नेट की तस्करी रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। हाल ही में उसने इसकी अवैध ढुलाई पर कार्रवाई कर सख्त कदम उठाए हैं और दुर्लभ खनिजों के उत्पादन तथा वितरण की निगरानी के लिए एक प्रणाली भी स्थापित की है।

कहा जा रहा है कि चीन सरकार ने फॉक्सकॉन से अपने तकनीशियनों और इंजीनियरों को इसलिए वापस बुलाया था क्योंकि वह भारत में आईफोन की उत्पादन लागत को बढ़ाना चाहती थी। अब इन जानकारों को ताइवान और जापान से बुलाया जा सकता है, लेकिन इससे उत्पादन लागत दो से तीन गुना बढ़ जाएगी।

संरचनात्मक सुधारों पर जोर : निर्मला

बीएस संवाददाता

निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री

ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि व्यापार और वित्तीय नीतियां बाजार विविधीकरण, बुनियादी ढांचा विकास को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धात्मकता एवं उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए संरचनात्मक सुधारों को लागू करने पर केंद्रित है।

यह बैठक 5 जुलाई को रियो डी जनेरियो में आयोजित की गई थी। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के इस दृष्टिकोण पर जोर दिया कि ब्रिक्स समावेशी बहुपक्षवाद को आगे बढ़ाने के लिए महत्त्वपूर्ण मंच है। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा, 'विशेष रूप से जब वैश्विक संस्थाएं वैधता और प्रतिनिधित्व के संकट का सामना कर रही हैं, तो ब्रिक्स को आपसी सहयोग को मजबूत करते हुए विश्वसनीय सुधारों के साथ विकासशील देशों की आवाज को आगे बढ़ाकर उदाहरण पेश करना चाहिए।'

वित्त मंत्री ने कहा कि जलवायु और विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में दक्षिण-दक्षिण सहयोग महत्त्वपूर्ण बना हुआ है, लेकिन विकासशील देशों से यह उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि वे जलवायु कार्रवाई का मुख्य बोझ उठाएं। उन्होंने कहा, 'ब्रिक्स देश सतत विकास पर सहयोग को मजबूत करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं।' वित्त मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए निर्मला सीतारमण ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कैसे भारत ने मजबूत घरेलू मांग, विवेकपूर्ण मैक्रोइकॉनॉमिक प्रबंधन और लक्षित राजकोषीय उपायों के संयोजन से आर्थिक मोर्चे पर लचीलापन प्रदर्शित किया है।

ट्रंप ने अतिरिक्त शुल्क लगाने की दी धमकी

डॉनल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स समूह की 'अमेरिका विरोधी नीतियों' का साथ देने वाले देशों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने की धमकी दी है। ब्रिक्स समूह के ट्रंप का नाम लिए बिना शुल्क वृद्धि की निंदा करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह धमकी दी है। ब्रिक्स समूह में शामिल देशों के नेता छह-सात जुलाई को 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील में मिल रहे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया मंच 'ट्रुथ सोशल' पर रविवार रात को लिखा, ' ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों से जुड़ने वाले किसी भी देश पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। इसमें कोई अपवाद नहीं होगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद।'

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अलग से जानकारी दी कि अमेरिका सोमवार से विभिन्न देशों को शुल्क और समझौतों के सिलसिले में 'पत्र' भेजेगा। उन्होंने कहा, 'मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि दुनिया भर के विभिन्न देशों के साथ अमेरिका के शुल्क पत्र और/या समझौते सोमवार सात जुलाई को दोपहर 12:00 बजे (पूर्वी समय) से वितरित किए जाएंगे। इस मामले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड जे. ट्रंप।' **भाषा**

दलाई लामा को बधाई पर चीन की आपत्ति

चीन ने सोमवार को कहा कि उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दलाई लामा को उनके 90वें जन्मदिन पर बधाई देने तथा समारोह में भारतीय अधिकारियों की उपस्थिति को लेकर भारत के समक्ष विरोध दर्ज कराया है।

चीन ने इस बात पर जोर दिया कि भारत को तिब्बत से संबंधित मुद्दों पर चीन की संवेदनशीलता को पूरी तरह समझना चाहिए। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि तिब्बत से संबंधित मामलों पर चीन की स्थिति सुसंगत और स्पष्ट है तथा यह सभी को पता है। माओ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दलाई लामा को उनके 90वें जन्मदिन पर बधाई देने तथा उनके जन्मदिन समारोह में वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों की उपस्थिति के बारे में पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि 14वें दलाई लामा राजनीतिक निर्वासन में हैं, जो लंबे समय से अलगाववादी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं और धर्म की आड़ में शिजांग को चीन से अलग करने का प्रयास करते रहे हैं। चीन तिब्बत को शिजांग कहता है।

उन्होंने कहा कि भारत को शिजांग से संबंधित मुद्दों की संवेदनशीलता को पूरी तरह समझना चाहिए तथा 14वें दलाई लामा की अलगाववादी प्रकृति को पहचानना चाहिए और शिजांग से संबंधित मुद्दों पर चीन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करना चाहिए। भारत को विवेकपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए और बोलना चाहिए तथा इस मुद्दे का इस्तेमाल चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं करना चाहिए। **भाषा**

डंपिंग रोकने की कोशिश, बांग्लादेश से कम जूट मंगवा रहा भारत

जयंत पंकज

डंपिंग रोकने और अपने किसानों की रक्षा के लिए भारत द्वारा हाल ही में बांग्लादेश से जूट का आयात बंद करने का फैसला एक बार फिर सुर्खियों में है। बीते वित्त वर्ष 2025 में भारत ने करीब 26.6 करोड़ डॉलर के जूट का आयात किया था और इनमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी बांग्लादेश (77 फीसदी) की थी। उसके बाद नेपाल (20 फीसदी) और चीन (0.2 फीसदी) का स्थान था।

भारत के इस फैसले से बांग्लादेश के समक्ष चुनौती खड़ी हो गई है, जिसने वित्त वर्ष 2024 में दुनिया भर में करीब 79.3 करोड़ डॉलर के जूट का निर्यात किया था और इसमें करीब एक चौथाई निर्यात भारत को किया गया था। इस असर को कम करने के लिए बांग्लादेश को अब नए व्यापार भागीदारों का रुख करना पड़ सकता है। इस बीच, भारत का जूट निर्यात उसके आयात से अधिक हो गया है और वित्त वर्ष 2024 में भारत के प्रमुख खरीदारों में अमेरिका (23 फीसदी), फ्रांस (9 फीसदी) और नीदरलैंड (6 फीसदी) शामिल हैं।

इसके अलावा भारत मुख्य रूप से बांग्लादेश, नेपाल और चीन से ही कुल मिलाकर जूट का आयात करता है। भारत के कुल जूट आयात में बांग्लादेश से आने वाले जूट की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2019 के 68 फीसदी से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 81 फीसदी हो गई थी। हालांकि, इस बीच कुछ उतार-चढ़ाव भी देखे गए और वित्त वर्ष 2025 में यह कम होकर 77 फीसदी रह गया।

जूट की विभिन्न श्रेणियों में बांग्लादेश से आयात होने में सर्वाधिक 38 फीसदी हिस्सेदारी कच्चे अथवा सड़े हुए जूट की थी। इसके बाद अन्य जूट विनिर्माताओं की हिस्सेदारी करीब 32 फीसदी और जूट धागे की 27 फीसदी थी।

भारत जितना जूट आयात करता है उससे कहीं अधिक दूसरे देशों में निर्यात करता है। वित्त वर्ष 2019 में भारत ने करीब 24.7 करोड़ डॉलर के जूट बाहर भेजे थे, जो वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर 29.9 करोड़ डॉलर हो गया। इसके विपरीत, जूट का आयात वित्त वर्ष 2019 में 17 करोड़ डॉलर था, जो वित्त वर्ष 2024 में 30.1 करोड़ डॉलर हो गया और वित्त वर्ष 2025 में घटकर 26.6 करोड़ डॉलर रह गया।

www.bankofbaroda.in बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

निविदा सूचना

बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सुरक्षा विभाग, बीसीसी, मुंबई, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर भवन में सीसीटीवी उपकरणों की आपूर्ति, इंस्टॉलेशन और रखरखाव के लिए वेंडरों को सूचीबद्ध करने हेतु प्रतिष्ठित सेवा प्रदाताओं से सीलबंद निविदा आमंत्रित करता है। शुद्धिपत्र संख्या 1 एवं 2 बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

निविदा प्रस्तुत करने की संशोधित अंतिम तारीख: दिनांक 21.07.2025 दोपहर 1400 बजे तक है।

विस्तृत विवरण के लिए हमारी वेबसाइट **www.bankofbaroda.in/tenders/corporate-office** देखें।

स्थान : मुंबई
दिनांक: 08.07.2025

मुख्य सुरक्षा अधिकारी
बैंक ऑफ़ बड़ौदा,
बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, मुंबई

46/25-26

ऑनलाइन शॉपिंग और भुगतान के लिए केवल विश्वसनीय वेबसाइट और एप्लिकेशन का ही उपयोग करें। प्रत्येक एप्लिकेशन के लिए एक विशिष्ट और जटिल पिन या पासवर्ड सेट करें।

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
प्रधान कार्यालय : 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008
कॉरपोरेट कार्यालय : एनबीसीसी कार्यालय कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक 3, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली–110023
वेबसाइट : https://punjabandsindbank.co.in/
पी.एस.बी
जहाँ सेवा ही जीवन – ध्येय है

सूचना

विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य श्रव्य–दृश्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से 15वीं वार्षिक सामान्य बैठक

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि बैठक की सूचना में उल्लिखित किए जाने वाले कार्यों को परिचालित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य श्रव्य–दृश्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से **मंगलवार, 05 अगस्त, 2025 को प्रातः 11:00 बजे,** पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की 15वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एतदपश्चात यहाँ "ई–एजीएम" के रूप में संदर्भित) का आयोजन किया जाएगा।

ई–एजीएम के लिए मानित स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय होगा।

लाभांश तथा ई–एजीएम के कारण बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बही, **बुधवार, 30 जुलाई, 2025 से मंगलवार, 05 अगस्त, 2025** (दोनों दिवस शामिल) तक बंद रहेंगे।

इस संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों के अनुपालन में बैंक की ई–एजीएम की सूचना समाविष्ट वार्षिक रिपोर्ट 2024–25 की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ उन समस्त शेयरधारकों को भेजी जाएगी जिनके ई–मेल पते, बैंक आरटीए के पास पंजीकृत हैं और **गुरुवार, 10 जुलाई, 2025** तक निक्षेपागार (ओं) द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। अमूर्त रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों जिनके ई–मेल आईडी पंजीकृत नहीं है, से अनुरोध है कि अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से अपने ई–मेल पते, मोबाइल नंबर अपने निक्षेपागार (ओं) के पास पंजीकृत कराएं। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि अपनी धारिता को अमूर्तीकृत करें/बैंक के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबेल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट एनएच 2, सी–1 ब्लॉक एलएससी, सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058, ई–मेल **delhi@in.mpms.mufg.com** को अपने ई–मेल आईडी और मोबाइल नंबर प्रदान करें।

भौतिक रूप/इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक जिन्होंने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है और ईमेल द्वारा ई–एजीएम सूचना समाविष्ट वार्षिक रिपोर्ट 2024–25 प्राप्त करने के इच्छुक हैं, वे लिंक **https://web.in.mpms.mufg.com/EmailReg/Email_Register.html** पर क्लिक करके और उसमें निर्देशित अनुसार पंजीकरण प्रक्रिया का अनुसरण करके अपना ईमेल अस्थाई रूप से पंजीकृत करा सकते हैं।

शेयरधारक, किसी प्रकार का प्रश्न या समस्या होने पर **rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com** को ई–मेल कर सकते हैं या दूरभाष नंबर 022–49186000 पर संपर्क कर सकते हैं।

बैठक की सूचना, बैंक वेबसाइट **https://punjabandsindbank.co.in/** तथा शेयर बाजारों की वेबसाइट **www.bseindia.com/** और **www.nseindia.com/** पर भी अपलोड की जाएगी।

शेयरधारकों के पास इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से ई–एजीएम सूचना में उपवर्णित रूप में व्यवसायिक कार्यकलापों पर दूरस्थ रूप से मतदान का अवसर होगा। अमूर्त रूप, मूर्त रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक तथा वे शेयरधारक जिन्होंने अपने ई–मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, के लिए दूरस्थ मतदान करने की शिष्टता, ई–एजीएम सूचना में उपलब्ध कराई जाएगी। विवरण, बैंक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे इस प्रकार का विवरण प्राप्त करने के लिए बैंक वेबसाइट **https://punjabandsindbank.co.in/** का अवलोकन करें।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि बैंक, शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां नहीं भेजेगा।

बैंक के निदेशक मंडल ने 29 अप्रैल, 2025 को संपन्न अपनी बैठक में, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से होने वाली आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में बैंक के शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए प्रत्येक ₹ 10 अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर पर ₹ 0.07 के लाभांश की अनुशंसा की है। लाभांश जैसा कि बोर्ड द्वारा अनुशंसित है और यदि **मंगलवार, 05 अगस्त, 2025** को आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में अनुमोदित किया जाता है तो अभिलिखित तिथि यथा **मंगलवार, 29 जुलाई, 2025** के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक अथवा भौतिक रूप में बैंक के इक्विटी शेयर रखने वाले शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, यथा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद किसी कंपनी द्वारा भुगतान या संवितरित लाभांश, शेयरधारकों के लिए कर योग्य है। इसलिए बैंक को लाभांश के भुगतान के समय स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) करना होगा। टीडीएस की कटौती, शेयरधारकों की आवासीय स्थिति तथा उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए आवश्यक दस्तावेज और अधिनियम के प्रयोज्य प्रावधानों के अनुसार बैंक द्वारा स्वीकार किए जाने के अधीन होगी। तदनुसार, प्रयोज्य टीडीएस (यदि कोई हो) की कटौती के बाद बैंक द्वारा लाभांश का भुगतान किया जाएगा। इसलिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे हमारे रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को **https://web.in.mpms.mufg.com/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html** पर **मंगलवार, 29 जुलाई, 2025 को अपराह्न 05:00 बजे** तक या उससे पूर्व आवश्यक दस्तावेज/फॉर्म प्रस्तुत करें।

बैंक, आरटीए के पास उपलब्ध अभिलेख के आधार पर टीडीएस काटने के लिए बाध्य है और उसके बाद टीडीएस रिटर्न में संशोधन के लिए किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(साकेत मेहरोत्रा)
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 07 जुलाई, 2025

Lenders ask bidders to sweeten offers for JAL

CoC in final phase of assessing resolution plans from 5 shortlisted bidders

RUCHIKA CHITRAVANSHI & DEV CHATTERJEE
New Delhi/Mumbai, 7 July

The Committee of Creditors (CoC) of Jaiprakash Associates Ltd (JAL) is in the final phase of assessing resolution plans of five shortlisted bidders, with lenders prioritising upfront cash and urging bidders to sweeten their offers. In meetings held on Monday between the lenders and the bidders, the former discussed the structure and funding of the proposed resolution plans.

All bids, however, remain contingent on the outcome of a key legal case surrounding Jaiprakash's 1,000-hectare Sports City project in Greater Noida. In March, the Allahabad High Court had upheld a decision by the Yamuna Expressway Industrial Development Authority (Yeida) to cancel the land allotment. The matter is now pending before the Supreme Court.

The Adani group has emerged as the frontrunner with a ₹12,250 crore bid, including ₹3,500 crore in immediate cash payout. Adani's offer includes retaining ₹890 crore within the company post-acquisition and potentially absorbing ₹2,600 crore from the disputed Yeida land — subject to a favourable court verdict. Despite the legal overhang, sources say Adani's proposal is currently viewed by lenders as the most reliable due to its structure.

Insolvency in focus

- All bids hinge on SC verdict over Yeida land cancellation
- Adani leads with ₹12,250 cr bid, including ₹3,500 cr upfront
- Dalmia offers ₹14,500 cr, but value drops without Yeida land
- Lenders face up to 79% haircut on ₹59,000 cr claim

Dalmia Bharat has made the highest offer at ₹14,500 crore, but that includes the full value of the contested land. If the Supreme Court rejects the land claim, the bid reduces to ₹11,500 crore, which includes ₹8,000 crore to be paid in cash, ₹2,600 crore paid back from Yeida land, and the rest deferred over two-to-three years.

Anil Agarwal-owned Vedanta group has submitted a ₹13,500 crore bid, entirely conditional on winning the Yeida land case, among several other conditionalities. PNC Infratech's ₹10,240 crore proposal includes ₹1,040 crore upfront, with ₹5,100 crore payable over 24 months, and remaining over the next 10 years. Jindal Steel & Power Ltd (JSPL) has bid ₹11,000 crore, offering ₹6,500 crore upfront, and the rest conditional on Yeida settlement.

The Adani group, Dalmia, Vedanta, JSPL, and PNC Infratech did not comment on the ongoing negotiations.

Creditors' total admitted claims against Jaiprakash Associates stand at over ₹59,000 crore. In all offers, the banks will end up taking a haircut of up to 79 per cent.

The CoC will finalise the winning bid based on overall proposal value, upfront cash offered, and resolution structure. There will be voting on each resolution plan by the members of the CoC.

The company entered insolvency on June 3, 2024. Its asset base spans cement, real estate, infrastructure, hospitality, and marquee developments like Jaypee Greens, Wish Town, and the International Sports City near the upcoming Jewar Airport.

HC-ordered panel for weight loss drug may be set up by mid-July

SANKET KOUL
New Delhi, 7 July

Dose of scrutiny

- Panel could be led by Drug Controller General of India
- It could also include DGHS and officials from Department of Pharmaceuticals
- Pharma associations may join to give an industry viewpoint
- Panel set up after Delhi HC directive on misuse of GLP-1 drugs
- It has 3 months to respond to PIL seeking review of approvals

The Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) is likely to begin work on forming a court-ordered expert panel to study the unregulated use of weight-loss drugs by mid-July, according to sources.

Officials in the know told *Business Standard* that the panel could be led by the Drug Controller General of India (DCGI) and may include representatives from the Directorate General of Health Services and the Department of Pharmaceuticals.

"There are discussions that pharmaceutical associations may also be asked to join to provide an industry viewpoint," an official aware of the matter said.

The CDSCO had not responded to queries emailed by Business Standard until the time of going to press.

Last week, the Delhi High Court directed the DCGI to consult experts and relevant stakeholders on the matter within three months. The panel is also expected to examine the possible unregulated use of antidiabetic drugs for weight loss within the court-mandated three-month deadline to respond to the petitioner.

The directive came in response to a public interest litigation filed by fitness entrepreneur Jitendra Chouksey, who raised concerns about the marketing approval of drugs such as semaglutide, tirzepatide, and liraglutide for weight management, despite limited safety data and the absence of India-specific clinical trials.

The order comes close on the heels of several weight loss drug launches by multinational pharmaceutical companies in India. US-based Eli Lilly launched Mounjaro (tirzepatide) in March, while Danish drugmaker Novo Nordisk introduced Wegovy (semaglutide) last month.

These once-a-week injectable drugs belong to a class of therapies known as glucagon-like peptide-1 receptor agonists, which help regulate blood sugar and slow digestion, making people feel fuller for longer.

According to standard guidelines for obesity medications, weight loss drugs are approved for patients with a body mass index over 27, along with at least one obesity-related comorbidity such as Type 2 diabetes, hypertension, or high cholesterol.

89% of FIIs in realty came from US, Japan, HK in Apr-Jun

SANKET KOUL
New Delhi, 7 July

The United States (US), Japan and Hong Kong accounted for 89 per cent of the total foreign institutional investment in India's real estate market for the April to June period (Q2 2025), according to a report by workplace solutions firm Vestian.

The three countries drove an increase in foreign investments which grew 242 per cent quarter-on-quarter (Q-o-Q) from $347 million in Q2 2024 to $1.19 billion in Q2 2025.

However, institutional investment in the Indian realty markets fell by 42 per cent year-on-year to $1.80 billion in Q2 2025, from $3.12 billion recorded for the same period last year over a drop in investment across all investment types.

This comes even as investments more than doubled sequentially, recording a 122 per cent growth over the Q1 2025 due to better foreign performance.

The report added that domestic investors accounted for just 19 per cent of the total investments in Q2 2025, down from 21 per cent in the same period last year. In value terms, domestic investments stood at $336 million.

GCCs propelled leasing of office space in Q2CY25

ANEEKA CHATTERJEE
Bengaluru, 7 July

Fuelled by the global capability centre (GCC) boom, gross leasing of office space across top eight cities soared 5 per cent to touch 21.4 million square feet (msf) in the second quarter of calendar year 2025, according to Cushman & Wakefield's Q2 India Office Market report.

GCCs contributed 24 per cent of Q2 leasing at 5.1 msf, led by Bengaluru and Pune. H1 2025 saw a record 11.4 msf in GCC leasing, driven by IT-BPM and E&M. IT-BPM remained the top occupier with 34 per cent demand, followed by flex operators (18 msf) and BFSI and Engineering and Manufacturing sectors.

With total leasing at approximately 42 msf, the sector is on pace to exceed 90 msf in annual activity, potentially setting a new record.

In terms of cities, Bengaluru (5.0 msf), Delhi NCR (4.6 msf), and Mumbai (3.9 msf) accounted for approximately 63 per cent of the total quarterly leasing volume. The remaining share came from Pune (3.3 msf), Chennai (2.2 msf), Hyderabad (1.7 msf), Kolkata (0.5 msf), and Ahmedabad (0.2 msf).

Every hotel brand of IHCL is growing, says Chandrasekaran

ROSHNI SHEKHAR
Mumbai, 7 July

The Indian Hotels Company Ltd (IHCL), with various brands like Taj, Gateway, Vivanta, and Ginger, among others, is observing growth in all its brands. But the mid-scale brand, Ginger, is growing at a faster pace due to management contracts, said N Chandrasekaran, non-executive director and chairman, IHCL, at the annual general meeting.

"Every hotel brand is growing. Ginger will obviously grow fast because it is growing a lot under the management contract, and also the size of investment is less (compared to other brands)," Chandrasekaran told shareholders. He added that the Taj brand will grow, but at a slower pace. Tata Group-owned IHCL has 103 Ginger-branded hotels as of April 2025, according to its investor presentation.

In the last financial year (FY25), the company signed 74 new hotels and had 26 new openings, taking the overall portfolio to 380 hotels. He further noted that the hotel's strategy is to have the right price levels for different customers, with hotels of different sizes (room capacity).

IFCI LIMITED
आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of india Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)

Regd. Office: IFCI Tower, 61 Nehru Place, New Delhi-110019
Tel: 011-41732000
Fax: 011-26230201
Website : www.ifciltd.com
CIN: L74899DL1993GOI053677

Tender No: IFCI/HO/CML&R/03/2025-26, dated 08/07/2025
SALE OF IFCI's INVESTMENT IN EQUITY SHARES OF NEELACHAL ISPAT NIGAM LIMITED UNDER SWISS CHALLENGE METHOD

IFCI Ltd. invites bids for sale of the following investment through a Swiss Challenge Process on 100% cash basis:

INVESTMENT	Offer in Hand (Rs.) ("Reserve Price")	Terms of Sale
22,92,501 (nos.) of Equity Shares of Neelachal Ispat Nigam Limited (NINL) of face value Rs.10/- each	17,42,30,076/-	100% cash basis

The Tender Document with detailed terms and conditions for the same has been uploaded on the website (http://www.ifciltd.com) under Tenders→Sale of Assets→NPA. Last date for submission of EOI is 15/07/2025 up to 5:00 PM. The bidding will take place on 24/07/2025.

All corrigenda/addenda/amendments/time extensions/clarifications etc., if any, to the tender will be hosted only at the website (http://www.ifciltd.com).

Note: IFCI reserves the right to reject all or any bid(s), wholly or partly without assigning any reason whatsoever.

Place: New Delhi
Date: 08/07/2025
Sd/-
DeputyGeneral Manager (CML&R)

Nahar SPINNING MILLS LIMITED
CIN: L17115PB1980PLC004341
Regd. Office: 373, Industrial Area-A, Ludhiana-141003
Phone : 0161-2600701-705, Fax : 0161-2222942
E-mail : secnsm@owmnahar.com, Website : www.owmnahar.com

Special Window for Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares

Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025, the Company is pleased to offer an one time special window for physical shareholders to submit re-lodgement requests for the transfer of shares.

This Special Window will open from July 07, 2025 to January 06, 2026 and is specially applicable to cases where the original share transfer requests were lodged prior to April 01, 2019, and were returned or rejected due to deficiencies in documentation, process or any other reason.

The shares re-lodged for transfer will be processed only in dematerialized form during this window.

Eligible shareholders may submit their transfer requests alongwith the requisite documents to the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) at M/s. Alankit Assignments Limited, Unit: Nahar Spinning Mills Ltd. 4E/2, Alankit House, Jhandewalan Extension, New Delhi - 110055 (Tel. 011-42541234), within the stipulated period.

For Nahar Spinning Mills Limited
Sd/-
Brij Sharma
Company Secretary & Compliance Officer
Place: Ludhiana
Dated : 05.07.2025

ANDHRA PRADESH POWER DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

E-PROCUREMENT NOTIFICATION

APPDCL invites Tender for "Supply of Elecon make Roller Screen Spares (CS Roll Body) for Coal handling plant of SDSTPS" through AP e-Procurement platform vide NIT No.M100027538. For Further details, please visit: **www.apgenco.gov.in** OR **https://tender.apeprocurement.gov.in/**

Ro.No. 4242PP/CL/ADVT/1/1/2021-22, Date- 07.07.2025
CHIEF ENGINEER/ O&M/SDSTPS

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! **punjab national bank** ...the name you can BANK upon !

STRESSED ASSET MANAGEMENT DIVISION (SAMD), HEAD OFFICE
PLOT NO.4, SECTOR-10, DWARKA, NEW DELHI-110075

PUBLIC NOTICE

Punjab National Bank intends to transfer/ assign NPA Accounts under section 5 of SARFAESI Act, 2002 on 100% cash basis on `as is where is', `as is what is' and `whatever there is' and without recourse basis. Expression of interest is invited from ARCs/Permitted Transferees for the accounts as under:

Sr No.	SAMB	Name	Book O/s as on 31.03.2025 (₹ in Crores)
1	Chandigarh	Imperial Fabrics (P) Ltd	10.18
2	Chennai	Vibha Agrotech Ltd	179.75
3	Chennai	NCSSugars Limited	105.44
4	Chennai	Aban Offshore Ltd	355.90
5	Chennai	Golden Jubilee Hotels Limited	102.87
6	Chennai	NSL Textiles Limited	48.77
7	Delhi	Wianxx Impex Private Limited	61.78
8	Delhi	Rangoli International Private Limited	67.43
9	Delhi	Supreme Alloys Limited	56.02
10	Delhi	Gupta Marriage Halls P Ltd.	13.47
11	Delhi	Bhadra International India Private Ltd	48.67
12	Delhi	Simbhaoli Sugars Limited	226.44
13	Delhi	Tasty Dairy Specialities Limited	52.54
14	Delhi	Raheja Developers Ltd.	169.11
15	Delhi	Entertainment City Limited	714.53
16	Delhi	Moser Baer Solar Ltd Formerly P V Technologies India Ltd	236.15
17	Delhi	Supertech Township Project Limited	71.94
18	Delhi	Supertech Realtors Pvt Ltd	96.23
19	Delhi	Millennium City Expressways Pvt Ltd	210.74
20	Delhi	Seven Seas Hospitality Pvt Ltd	75.90
21	Delhi	Suratgarh Bikaner Toll Road Company Private Limited	90.36
22	Kolkata	Corporate Power Limited	195.07
23	Kolkata	Kohinoor Steel Pvt Ltd	21.54
24	Kolkata	Shree Parashnath Re-Roolling Mills Ltd	12.95
25	Kolkata	Ambootia Tea Exports Pvt Ltd	125.41
26	Kolkata	Concast Path Bameetha Satna Road Projects Pvt Ltd	65.30
27	Mumbai	Wizcraft international Entertaintment Private Limited	9.38
28	Mumbai	Core Education and Technologies Ltd.	99.57
29	Mumbai	Sanwaria Consumer Limited	245.27
30	Mumbai	Distribution Logistics Infrastructure Private Limited	166.49
31	Mumbai	Birla Surya Ltd	138.85

Interested ARCs/Permitted Transferees can send their expression of interest at **hosastraarc@pnb.co.in**. PNB reserves the right to cancel/modify/withdraw the process and amend at any stage at Bank's discretion without citing any reason thereto. In case of any clarification, you may contact the undersigned:

Name	Designation	Contact details
Mrityunjay Kumar	Dy. General Manager	7506647014
Dheeraj Jha	Asst General Manager	9909994101

The last date for submission of expression of interest shall be 15.07.2025 (Tuesday) by 05.00 PM.

For more details please visit 'Public Notices' section on Bank's corporate website https://www.pnbindia.in/Public-Notices.aspx .

Place: New Delhi
Date:07.07.2025
Sd/-
Asstt. General Manager

੧ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ

Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)
Head Office: 21-Rajendra Place, New Delhi-110008.
Corporate Office: NBCC Office Complex, Block 3, East Kidwai Nagar, New Delhi - 110023
https://punjabandsindbank.co.in/
पी.एस.बी
Where service is a way of life

NOTICE

15th ANNUAL GENERAL MEETING
THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM)

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 15th Annual General Meeting of the Shareholders of PUNJAB & SIND BANK will be held on **Tuesday, the 5th day of August, 2025 at 11.00 a.m.** through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) (hereinafter referred to as "e-AGM") to transact business that will be set forth in the Notice of the Meeting.

The deemed venue for the e-AGM shall be the Head Office of the Bank.

The Register of Shareholders and the Share Transfer Books of the banks will remain closed from **Wednesday, July 30, 2025 to Tuesday, August 5, 2025** (both days inclusive) in connection with the Dividend and e-AGM.

In compliance with the various Circulars issued by Securities & Exchange Board of India (SEBI) and Ministry of Corporate Affairs (MCA) in this regard, electronic copies of the Annual Report for 2024-25 containing the Notice of the e-AGM of the Bank will be sent to all the shareholders whose email addresses are registered with the Bank's RTA and as provided by the Depositories as on **Thursday, 10 July, 2025.** Shareholders holding shares in the dematerialized mode and whose email ids are not registered are requested to register their email addresses, mobile numbers with their depositories through their Depository Participants. Shareholders holding shares in physical mode are requested to demat their holdings / furnish their email addresses and mobile numbers to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, Link Intime India Pvt. Ltd, Noble Heights, 1st Floor, Plot NH 2, C-1 Block LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi – 110058 Email: **delhi@in.mpms.mufg.com**.

Shareholders holding shares in physical mode / electronic mode who have not registered their email ids and are desirous of receiving the Annual Report 2024-25 containing the Notice of the e-AGM by email may get their email temporarily registered by clicking the link **https://web.in.mpms.mufg.com/EmailReg/Email_Register.html** and follow the registration process as guided therein.

In case of any queries, shareholder may write to **rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com** or call on Tel no.: 022-49186000;

The Notice of the meeting will also be uploaded on the Banks website **https://punjabandsindbank.co.in/** and on the websites of the Stock Exchanges at **www.bseindia.com/** and **www.nseindia.com/**.

Shareholders will have an opportunity to cast their vote remotely on the business as set forth in the notice of the e-AGM through electronic voting system. The manner of remote voting for the shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses will be provided in the e-AGM notice. The details will be made available on the Banks Website. Shareholders are requested to visit the Banks website **https://punjabandsindbank.co.in/** to obtain such details.

Shareholders may please note that the Bank will not be sending physical copies of the Annual Report to the shareholders.

The Board of Directors of the Bank at its meeting held on 29th April 2025 recommended a dividend of Rs. 0.07 per equity share of face value of Rs. 10 each for the Financial Year 2024-25 subject to the approval of the shareholders of the Bank at its ensuing Annual General Meeting to be held through VC / OAVM. The dividend, as recommended by the Board and if approved at the ensuing Annual General Meeting on **Tuesday, 5 August, 2025**, will be paid to the shareholders holding equity shares of the Bank either in electronic or in physical form as on the record date i.e., **Tuesday, 29 July, 2025**.

Further, in terms of the provisions of the Income Tax Act, 1961 (The Act), as amended, dividend paid or distributed by a company on or after April 1, 2020 is taxable in the hands of the shareholders. The Bank shall therefore be required to deduct tax at source (TDS) at the time of payment of dividend. Deduction of TDS would depend on the residential status of the shareholders and the necessary document submitted by them and accepted by the Bank in accordance with the applicable provisions of the Act. Accordingly, the dividend will be paid by the Bank after deducting applicable TDS, if any. Shareholders are therefore requested to furnish the necessary documents / forms to our Registrar and Share Transfer Agent, Link Intime India Pvt Ltd at **https://web.in.mpms.mufg.com/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html on or before 05:00 p.m. on Tuesday, 29 July, 2025.**

The Bank is obligated to deduct TDS based on the records available with RTA and no request will be entertained for revision of TDS Return thereafter.

By order of the Board of Directors
For PUNJAB & SIND BANK
(Saket Mehrotra)
Company Secretary
Place: New Delhi
Date: 07 July, 2025

Navigate markets with focused insight.

Get daily sector trends, market movers, and sharp insights — *every day* with **The Compass** in Business Standard.

To book your copy, SMS **reachbs** to **57575** or email **order@bsmail.in**

Business Standard
Insight Out

SALE NOTICE UNDER IBC, 2016

M/s. KONASEEMA GAS POWER LIMITED (KGPL) (In Liquidation) CIN: U40101TG1997PLC037013
Regd. Office: # Progressive Towers 6-2-913/914, Khairathabad, Hyderabad-500004, Telangana.

Bids are invited through e-auction platform https://ibbi.baanknet.com for sale of assets of KGPL forming part of Liquidation Estate by Liquidator U/s. 35 (f) of IBC, 2016 reg. 33(1) of IBBI (Liquidation Process), Regulations 2016.

Lot No.	SALE OF ASSETS OF KGPL SITUATED AT RAVULAPALEM, Dr. B.R. AMBEDKAR KONASEEMA DT. (FORMER EAST GODAVARI DT), A.P. AS PER REGULATION 32 (a) to (d)	Reserve Price (Rs. Cr)	EMD (Rs.Cr)	Incremental BID Amount (Rs. Cr)
I	445 MW Natural Gas based Combined Cycle Power Plant (P&M) comprising of 2 Gas Turbines (Siemens, V94.2)-139.44 MW each + 2 HRSG + 1 Steam Turbine (LMZ, Russia) - 166.60 MW, Land around 128.16 Acres (including road, pipe area, APTRANSCO towers area) and Factory Buildings & all other equipment at plant site.	227.61	5	2
II	Land around 5.80 Acres Kotha Peta Village, abutting power plant land Sy nos. 7/1, 6/2B, 6/3B, 7/4 Kotha Peta. and 36/2, Devarapalli village.	9.45	0.945	0.03

Last date for submission of EOI with all bid documents and EMD as per the e-Auction Process Information Document.	29.07.2025
Date of e-Auction & Timing:	FOR BOTH LOTS-I & II: 31.07.2025 {10 AM to 4 PM} (With unlimited extension of 5 minutes each up to 7pm for both Lots I & II)

1. Interested applicants may refer relevant E-AUCTION PROCESS INFORMATION DOCUMENT (I) for Lot-I and E-AUCTION PROCESS INFORMATION DOCUMENT (II) for Lot-II as the case may be, with terms and conditions of online E-Auction, Bid form, Eligibility Criteria, Declaration by Bidders, EMD requirement etc., available at https://ibbi.baanknet.com , www.konaseemapower.com .
2. Prospective bidders shall submit the requisite documents, including an undertaking of eligibility under Section 29A of the Insolvency and Bankruptcy Code through the BAANKNET auction platform: https://ibbi.baanknet.com .
3. Prospective bidders shall deposit the Earnest Money Deposit (EMD) through the BAANKNET auction platform: https://ibbi.baanknet.com .
4. The undertaking referred in clause 2 hereinabove should state that the prospective bidder does not suffer from any ineligibility under section 29A of the Code to the extent applicable and that if found ineligible at any stage, the Earnest Money Deposited (EMD) shall be forfeited.
5. The maximum time allowed to the Successful Bidder for making payment of balance Sale Consideration (i.e., accepted Bid Amount plus other applicable taxes/ duties after set-off / adjustment of EMD received) along with interest due is 120 days from the date of LOI.
6. Interested applicants requiring assistance in submitting the BID forms and EMD may contact the **Liquidator @ 98490 39674 -- e-Mail email: info@ksrfms.com / liqkgp@gmail.com or his authorized representatives CS Sridhar @ 92462 01960 / Mr. K Vijay @ 94917 91079 or Mr. Kashyap Patel @ 9327493060 - e-Mail: support.BAANKNET@psballiance.com** .
7. It is clarified that, this invitation purports to invite prospective bidders and does not create any kind of binding obligation on the part of the Liquidator or the Company to effectuate the sale. Liquidator has the right to extend /defer /cancel and/or modify, delete any of the terms and conditions including timelines of E-Auction at his discretion in the interest of Liquidation Process and has right to reject any bid without any prior notice or assigning any reason whatsoever at any stage of the auction.
8. E-Auction shall be conducted on **"AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" "WHATEVER THERE IS" and "NO RECOURSE" basis** only.

Date: 08-07-2025
Place: Hyderabad
Sd/- CA. SAI RAMESH KANUPARTHI, Liquidator:
IBBI Reg No.: IBBI/IPA-001/IP-P00910/2017-2018/11510
(Authorisation for Assignment valid up to 31.12.2025)
Address for Correspondence: Plot 6-B, Road No.2, Banjara Hills, Hyderabad-500034. Cell: 9849039674

PUBLIC NOTICE

It is informed to the public that my client State Bank of India, RACPC-2, Correnthum Building, Sector-62, Noida has sanctioned the Housing Loan to Shri Neeraj Garib s/o Shri Pran Nath Garib for the property situated at Flat no. 1106 B1, T-1, 11th Floor, Super area 1025 sq. ft. situated at Plot no. 18A, Vaibhav Khand, Indirapuram, Ghaziabad. My Client has lost the Original Sale Deed executed by Shri Chiranjiv Kumar Sharma & Smt. Charu Sharma in favour of Shri Neeraj Garib vide Sale Deed registered on dated 28.07.2008, in the office of Sub Registrar- IV, Ghaziabad in book no. I volume no. 11053 on pages 341-372 vide Document no. 20979.

If anybody dealing or misusing the above said property documents, my client shall have first exclusive right on the said property. It is also to be noted that the said property will be treated as unencumbered (except the charge of my client), marketable and no claim will be accepted on the basis of aforesaid document here in above.

ANKUR JINDAL, (ADVOCATE)
B-215, LOHIA NAGAR
GHAZIABAD- 201001